देश में छावनी क्षेत्रों में जन सुविधाओं का अभाव

792. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निधियों के अभाव के कारण देश में सभी छावनी क्षेत्रों में पर्याप्त रूप में बुनियादी जनसुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप वहां के निवासियों को सड़कों, जल निकास और पीने के पानी आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या इस प्रयोजन के लिए कोई तकनीकी/वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए छावनी बोर्डों को धन उपलब्ध होने पर सहायता अनुदान दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में विस्थापित कृषकों का पुनर्वास

793. श्री अजीत जोगी : क्या **प्रधान मंत्री** 11 अगस्त, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2063 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित उस योजना को स्वीकृति दे दी है जो इन्दौर जिले के 24 गांवों के उन विस्थापित कृषकों के पुनर्वास से संबंधित थी जिनकी भूमि का रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिगृहण कर लिया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने का प्रस्ताव है, इस योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों का पुनर्वास किया जायेगा और उनका किस तरह से पुनर्वास किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) सरकार ने 12 गांवों के उन विस्थापित कृषकों के पुनर्वास के लिए 2.9.88 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं जिनकी भूमि "बेइरचा फील्ड फायरिंग रेंज" के लिए अधिकृत की गई थी। "हेमा फील्ड फायरिंग रेंज" के लिए 12 गांवों में भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिग्रहण की कार्रवाई को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए उन प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता जिनकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है।

(ख) इसका संबंध मध्य प्रदेश की सरकार से है।

Increase in defence allocation

794. SHRI SYED SIBTEY RZAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the defence allocations;

(b) if so, what are the details thereof and in what context this increase is envisaged;

(c) whether this increase would in any way enable to check infiltration of trained terrorists from across the borders; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) and (b) Government maintains a close watch on the emerging security environment. As and when it becomes necessary to increase the defence allocation, supplementary grants are sought from Parliament.

(c) and (d) Appropriate precautionary measures are taken to protect the inviolability of our borders.

Vacant post of Chairman of Kendriya Vidyalaya Sangathan

795. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there had been a regular Chairman of Kendriya Vidyalaya Sangathan between December, 1989 to March, 1990; and

(b) if not, the reasons for not filling the post?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) By virtue of Rule 3 of Kendriya Vidyalaya Sangathan Rules, Prime Minister in his capacity as Minister in charge of Education and Kendriya Vidyalaya Scheme was the Chairman Subsequently w.e.f. 19-3-1990, the Minister of State in charge of Education was designated as Chairman.

796. [*Transferred to the 23rd May 1990*]

Evaluation of Bids for 155 MM Howitzer Guns

797. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1735 given in the Rajya Sabha on the 27th March, 1990 and state:

(a) what are the dates on which evaluation of bids for 155 mm Howltzer Guns including its live demonstrations, were first evaluated and the status of the respective bidders therein:

(b) what are the details of subsequent revisions in prices and specifications offered by the bidders: and

(c) what is the value of counter trade envisaged in the deals for purchase of Bofors Gun?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) to (c) 1. 155 mm Towed Guns offered by the following seven parties were trial evaluated in India on the dates shown against each:—

(i) M-65 (Yugoslavia)	June-July 1978
(ii) FH 70 (UK)	March-May 1980
(iii) M 198 (USA)	April-June 1980
(iv) FH 77B (Sweden)	June-December, 1981
(v) GC-45 (Austria)	September-November 1981
(vi) M 114 (Netherlands)	March-April 1982
(vii) TR (France)	March-April 1982

2. A Delegation of the Army also witnessed firing/demonstrations of FH 70 (UK), FH 77B (Sweeden) and SG-45 (Austria) during its visits to these countries in June-July 1982 to verify whether certain modifications required to be carried out had been incorporated in the guns by the concerned firms. Based on these trials and demonstrations the Army Headquarters prepared a General Staff Evaluation Report on 31st December, 1982 in which the following guns in the order of preference were recom-